संख्या-133 /2024/386/नौ-9/003-E-1721372

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 27, फरवरी, 2024**

विषय:-15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वर्ष 2023-2024 हेतु प्रदेश के Million Plus शहर के लिये संस्तुत Air Quality Improvement मद की धनराशि रू0 15650.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0सी0ए0 37/दस-2024-02/2020, दिनांक-23.02.2024 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-22.02.2024 (**छायाप्रति संलग्न**) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत Million Plus शहरों के लिये Air Quality Improvement मद में उपलब्ध/अवशेष धनराशि में से **कुल धनराशि रू0 15650.00 लाख (रू0 एक अरब छप्पन करोड़ पचास लाख मात्र)** 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (**नगर निगम, आगरा, प्रयागराज, कानपुर, एवं वाराणसी)** (Urban Agglomeration) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को आवंटित करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की मा0 राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस शर्त के साथ रखी जा रही है कि आपके द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों/नीतियों को अक्षरशः पालन करते हुये, भारत सरकार के पत्र दिनांक-22.02.2024 में उल्लिखित शर्तों एवं निर्धारित मानक के अनुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों (नगर निगम आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं वाराणसी) एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) को बिना किसी कटौती के निर्धारित समयान्तर्गत (10 कार्य दिवस के अन्दर) उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अवमुक्त उक्त धनराशि का उपभोग वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-एफ15(2) एफसी-XV/एफसीडी/2020-25, दिनांक-28.07.2021 द्वारा निर्गत Operational Guideline के प्राविधानों एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार (MOEF & CC) द्वारा समय-समय पर की गयी संस्तुतियों/15वें वित्त आयोग के अध्याय-7 (Chapter-7) द्वारा निर्धारित मापदण्डो के अनुसार ही अनुमन्य होगा।

(3) उक्त धनराशि का कोषागार से आहरण करके निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा नागर स्थानीय निकायों के 15 वें वित्त आयोग से संबंधित खुले खाते में इलेक्ट्रानिक माध्यम से निर्धारित समयान्तर्गत अन्तरित कराया जाय।

(4) केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तर-5.3 के बिन्दु संख्या-XII में मिलियन प्लस सिटीज के अतिरिक्त अन्य सिटी हेतु धनराशि के वितरण की प्रक्रिया का उल्लेख है, जिसके अनुसार धनराशि का आवंटन किया जायेगा।

(i) कैण्टोनमेन्ट बोर्ड (यदि कोई हो) के मध्य पारस्परिक आवंटन Inter-Se Distribution केन्द्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कैण्टोनमेन्ट बोर्ड की जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

(5) The Ambient Air Quality Grant for Million-Plus Cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide Letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 10-08-2021 and recommendations contained in chapter-7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

(6) FC-XV recommended above mentioned Ambient Air Quality grant for Million-Plus Cities is intended to be utilized for air quality improvement measures as stipulated in the approved City Action Plan (CAP), on achieving measurable outcomes in reducing Concentration of particulate matter and for the measures stipulated in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for improving air quality.

(7) The state Governments (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to the concerned Million-Plus City/UA as mentioned against each such city above in column 6 within 10 working days of receipt from the Union Governments without any deduction. In the case of urban agglomerations, which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust one urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration. However, Some cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such ULBs(NMPCs) on the basis of accepted recommendation of the lates State Finance Commission (SFC). In case of non-availability of SFC recommendations for the distribution within a particular category, the allocation should be done on the basis of population Census, 2011 and area in the ratio of 90:10.

(8) Any delay beyond ten working days will require the State Government to release the grant with interest as per the average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

(9) The State Governments/urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Accounts of each recipient entity/ULB has been opened in any scheduled Commercials banks for FC-XV recommended Ambient Air Quality grant and the same is linked with PFMS and maintained for every transaction for the full award period.

(10) धनराशि के आहरण की सूचना बाउचर संख्या व दिनांक सहित वित्त विभाग व नगर विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(11) टेण्डर की कार्यवाही केवल अनुमोदित कार्यों हेतु की जायेगी।

(12) इस अनुदान के लेखों का रख-रखाव संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस अनुदान के उपयोग एवं सम्प्रेषण की प्रणाली निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

-3-

(13) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत संस्तुत अनुदान राशि का उपयोग निर्धारित स्कीमों के अन्तर्गत किये जाने से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराये जाने होगे। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथाशीघ्र भारत सरकार को वित्त विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा।

(14) उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर निगमों के संबंध में नगर आयुक्त, एवं कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के माध्यम से निर्धारित प्रारूप पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

3. नगर निगमों के संबंध में संबंधित नगर आयुक्त तथा कैण्टोनमेन्ट बोर्ड के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह सुनिश्चित करेगे कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुरूप एवं समयबद्ध रूप से किया जाये। दिशा निर्देशों से हट कर किया गया व्यय अनुमन्य नहीं होगा तथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। इसके लिये संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217808000401 (आगरा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000401 आगरा	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)
	कुल			**50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000402 (प्रयागराज)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000402 प्रयागराज	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	25,50,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**25,50,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000404 (कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000404 कानपुर	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	41,00,00,000 (रुपये इकतालीस करोड़ मात्र)
	कुल			**41,00,00,000 (रुपये इकतालीस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217808000407 (वाराणसी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217808000407 वाराणसी	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)
	कुल			**40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)**

महायोग	**1,56,50,00,000 (रुपये एक अरब छप्पन करोड़ पचास लाख मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या E-9-538-X-2023-24- दिनांक: 27/02/2024** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
27.02.2024

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-133/2024/386/ग्या-9/003-E-1721372, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रांच)/ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) , प्रयागराज।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार, स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निदेशक (एफसीडी), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
5. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश शासन।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
7. वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता अनुभाग), उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,
27.02.2024

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A009-20232024-Reapp-1721372 M-Plus

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023—24 में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत '10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन' हेतु रू0 156.50 करोड़ की धनराशि के पुनर्विनियोग के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2215021070512 (01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी निकाय के लिए यूज्ड वाटर मैनेजमेंट संबंधी कार्य (के.50/रा.33/ला.17 - के.))	35 (पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)	5,39,70,62,572 रुपये पांच अरब उनतालीस करोड़ सत्तर लाख बासठ हजार पांच सौ बहत्तर मात्र	2,83,40,12,572 रुपये दो अरब तिरासी करोड़ चालीस लाख बारह हजार पांच सौ बहत्तर मात्र	-1,56,50,00,000 रुपये एक अरब छप्पन करोड़ पचास लाख मात्र	3,83,20,62,572	2023-2024

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
037	2217808000404 (कानपुर)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	3,26,31,90,000 रुपये तीन अरब छब्बीस करोड़ इकतीस लाख नव्वे हजार मात्र	41,00,00,000 रुपये इकतालीस करोड़ मात्र	3,67,31,90,000	2023-2024
037	2217808000402 (प्रयागराज)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	1,70,98,00,000 रुपये एक अरब सत्तर करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र	25,50,00,000 रुपये पच्चीस करोड़ पचास लाख मात्र	1,96,48,00,000	2023-2024
037	2217808000401 (आगरा)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,19,48,00,000 रुपये दो अरब उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख मात्र	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	2,69,48,00,000	2023-2024
037	2217808000407 (वाराणसी)	20 (सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन))	2,21,69,40,000 रुपये दो अरब इक्कीस करोड़ उनहत्तर लाख चालीस हजार मात्र	40,00,00,000 रुपये चालीस करोड़ मात्र	2,61,69,40,000	2023-2024

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-1 में अंकित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत भारत सरकार से केन्द्रांश की धनराशि प्राप्त न होने के कारण बचत हो रही है।

(2) 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत '10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों हेतु सहायता अनुदान-सामान्य गैर वेतन' हेतु के मद-20 में भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण अधिक धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक् त पुनर्विनियोग में उ.प्र. बजट मैनुअल के प्रस् तर- 150 व 151 में निर्दिष् ट प्रतिबन् धों/परिसीमाओं का उल् लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर.ई.-बजट-1- 494, दिनाँक 22.02.2024

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक।

संख्या: आर.ई.-बजट-1- 494, दिनाँक 22.02.2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4- मिशन निदेशक, एसबीएम 2.0, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- राज्य मिशन निदेशक, एसबीएम 2.0, /निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक/सहायक निदेशक (लेखा) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

27.02.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

386/नी-9-24

शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-एफ0सी0सी0ए0-37 /दस-2024-02/2020

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,

विशेष सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,

नगर विकास विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 23 फरवरी, 2024**

विषय: पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों (Million Plus Cities) हेतु वर्ष 2023-24 के लिये संस्तुत अनुदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 22 फरवरी, 2024 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की नगरीय स्थानीय निकायों (Million Plus Cities) हेतु Air Quality Improvement के लिए रू0 156.50 करोड़ अवमुक्त किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

2. कृपया उक्त स्वीकृत धनराशि को पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों एवं भारत सरकार के पत्र दिनांक 22-02-2024 के प्रस्तर- 2, 3, 4, 5 एवं 6 के अनुसार अवमुक्त किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक दीक्षित)

पत्र संख्या-एफ0सी0सी0ए0-37 (1)/दस-2024-02/2020 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि: विशेष सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक दीक्षित)

विशेष सचिव

23/02/24

ULB Release No.109/2023-24

AMOUNT TO BE CREDITED IN THE ACCOUNTS OF THE STATE GOVERNMENTS

F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

Block No. XI, 5th Floor,
CGO Complex,
New Delhi-110003.
Dated:-22-02-2024.

To,

The Accounts Officer (State- Loan),
O/o the Chief Controller of Accounts,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi -110001.

Subject:-Release of Urban Local bodies grant (Million Plus Cities) to the State Government (s) as recommended by the Fifteenth Finance Commission (FC-XV) for **Air Quality Improvement**.

Sir,

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India for release of **Rs. 15650.00 lakh** (Rupees One Hundred, Fifty-Six crore and Fifty Lakh only) to the State Government(s) as per details given below;

Release of Ambient Air Quality Grant to Million Plus Cities/agglomeration for the FY 2023-24.					
State S. No.	**Name of State**	**Amount of Ambient Air quality Grant released for the State (Rs.in crore)**	**City S. No.**	**Million Plus Cities / agglomeration**	MPC/UA wise grant distribution (Rs.in crore)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	**Uttar Pradesh**	**156.50**	1.	Agra U.A.	**50.00**
			2.	Allahabad U.A.	**25.50**
			3.	Varanasi U.A.	**40.00**
			4.	Kanpur U.A.	**41.00**
x	Total	**156.50**	x	**Total**	**156.50**

2. The Ambient Air Quality grant for Million-Plus cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 10-8-2021 and recommendations contained in Chapter 7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

3. FC-XV recommended above mentioned Ambient Air Quality grant for Million-Plus cities is intended to be utilized for air quality improvement measures as stipulated in the approved City Action Plan(CAP), on achieving measurable outcomes in reducing concentration of particulate matter and for the measures stipulated in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for improving air quality.

Contd. on next page-2.

4. The State Governments (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to the concerned Million Plus City/UA as mentioned against each such city above in column 6 within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction. In the case of urban agglomerations which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust one urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration. However, Some cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such **ULBs(NMPCs)** on the basis of accepted recommendations of the latest State Finance Commission (SFC). In case of non-availability of SFC recommendation for distribution within a particular category, the allocations should be done on the basis of population Census, 2011 and area in the ratio of 90:10.

5. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the grant with interest as per the weighted average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

6. The State Governments/Urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Account of each recipient entity/ULB has been opened in any Scheduled Commercial Bank for FC-XV recommended Ambient Air Quality grant and the same is linked with PFMS and maintained for every transaction for the full award period.

7. PAO-State Loan, O/o the Chief Controller of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi is requested to advise the Reserve Bank of India, Nagpur to credit the above amount to the accounts of the **respective State Government(s)**.

8. The payments are adjustable in the accounts of the Ministry of Finance in **Demand Grant No. 042** - Transfers to State Government(s) **for the year 2023-24** under Function Head 3601071030100, Object Head 31, Scheme code 2085 as Grants for Local Bodies(3.02 Urban Bodies).

(Anil Gairola)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

Sl. No.	Name
1	The Secretary, RBI, Central office, Mumbai.
2	The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi.
3	The Manager, RBI, Central Accounts Section, Nagpur.
4	The Budget Division (States Section), DEA, North Block, New Delhi.
5	The PAO-State loan, Department of Expenditure(DOE).
6	The Accountant General(A&E), concerned State Government(s).
7	The Accountant General(Audit), concerned State Government(s).
8	The Secretary (Finance), concerned State Government(s).
9	The Secretary(Urban Department), concerned State Government(s).
10	Hindi Section, Department of Expenditure (for Hindi translation)

(Anil Gairola)
Deputy Secretary to the Government of India

ULB Release No.109/2023-24

AMOUNT TO BE CREDITED IN THE ACCOUNTS OF THE STATE GOVERNMENTS

F.15(45)FC-XV/FCD/2020-25
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
Finance Commission Division

Block No. XI, 5th Floor,
CGO Complex,
New Delhi-110003.
Dated:-22-02-2024.

To,

The Accounts Officer (State- Loan),
O/o the Chief Controller of Accounts,
Department of Expenditure,
Ministry of Finance, North Block,
New Delhi -110001.

Subject:-Release of Urban Local bodies grant (Million Plus Cities) to the State Government (s) as recommended by the Fifteenth Finance Commission (FC-XV) for **Air Quality Improvement**.

Sir,

The undersigned is directed to convey the approval of the Competent Authority in the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India for release of **Rs. 15650.00 lakh** (Rupees One Hundred, Fifty-Six crore and Fifty Lakh only) to the State Government(s) as per details given below;

Release of Ambient Air Quality Grant to Million Plus Cities/agglomeration for the FY 2023-24.					
State S. No.	**Name of State**	**Amount of Ambient Air quality Grant released for the State (Rs.in crore)**	**City S. No.**	**Million Plus Cities / agglomeration**	MPC/UA wise grant distribution (Rs.in crore)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	**Uttar Pradesh**	**156.50**	1.	Agra U.A.	**50.00**
			2.	Allahabad U.A.	**25.50**
			3.	Varanasi U.A.	**40.00**
			4.	Kanpur U.A.	**41.00**
x	**Total**	**156.50**	x	**Total**	**156.50**

2. The Ambient Air Quality grant for Million-Plus cities/UAs will be governed as per the provisions in the Operational Guidelines issued on the subject by the Department of Expenditure vide letter No. 15(2)FC-XV/FCD/2020-25, dated 10-8-2021 and recommendations contained in Chapter 7 of FC-XV Report for the award period 2021-26.

3. **FC-XV recommended above mentioned Ambient Air Quality grant for Million-Plus cities is intended to be utilized for air quality improvement measures as stipulated in the approved City Action Plan(CAP), on achieving measurable outcomes in reducing concentration of particulate matter and for the measures stipulated in the tripartite Memorandum of Understanding (MoU) for improving air quality.**

22/2/24

Contd. on next page-2.

4. The State Governments (State Finance Department) shall transfer grants-in-aid directly to the concerned Million Plus City/UA as mentioned against each such city above in column 6 within ten working days of receipt from the Union Government without any deduction. In the case of urban agglomerations which contain more than one Million-Plus city, the concerned State Government, in consultation with all such entities within the urban agglomeration, shall entrust one urban local body as the nodal entity to receive the grants. This nodal entity will also have the responsibility of achieving the performance indicators for the entire urban agglomeration. However, Some cities and towns may be part of some urban agglomeration, these grants will also be distributed to such **ULBs(NMPCs)** on the basis of accepted recommendations of the latest State Finance Commission (SFC). In case of non-availability of SFC recommendation for distribution within a particular category, the allocations should be done on the basis of population Census, 2011 and area in the ratio of 90:10.

5. Any delay beyond ten working days will require the State Governments to release the grant with interest as per the weighted average effective rate of interest on market borrowings/State Development Loans (SDLs) for the previous year.

6. The State Governments/Urban Local bodies (recipient) shall have to ensure that a separate Account of each recipient entity/ULB has been opened in any Scheduled Commercial Bank for FC-XV recommended Ambient Air Quality grant and the same is linked with PFMS and maintained for every transaction for the full award period.

7. PAO-State Loan, O/o the Chief Controller of Accounts, Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi is requested to advise the Reserve Bank of India, Nagpur to credit the above amount to the accounts of the **respective State Government(s)**.

8. The payments are adjustable in the accounts of the Ministry of Finance in **Demand Grant No. 042** - Transfers to State Government(s) **for the year 2023-24** under Function Head 3601071030100, Object Head 31, Scheme code 2085 as Grants for Local Bodies(3.02 Urban Bodies).

(Anil Gairola)
Deputy Secretary to the Government of India

Copy to:

Sl. No.	Name
1	The Secretary, RBI, Central office, Mumbai.
2	The Secretary, Ministry of Housing & Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi.
3	The Manager, RBI, Central Accounts Section, Nagpur.
4	The Budget Division (States Section), DEA, North Block, New Delhi.
5	The PAO-State loan, Department of Expenditure(DOE)
6	The Accountant General(A&E), concerned State Government(s).
7	The Accountant General(Audit), concerned State Government(s).
8	The Secretary (Finance), concerned State Government(s).
9	The Secretary(Urban Department), concerned State Government(s).
10	Hindi Section, Department of Expenditure (for Hindi translation)

(Anil Gairola)
Deputy Secretary to the Government of India